

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 जनवरी 2023—माघ 7, शक 1944

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 दिसम्बर 2022

क्रमांक ई 1-19/2022/एक-2.—श्री धनंजय देवांगन, भा.प्र.से. (सीजी: 2004) द्वारा स्वैच्छापूर्वक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन दिनांक 02-12-2022 प्रस्तुत किया गया है. श्री देवांगन द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर पूर्ण विचारोपरान्त एवं शासकीय सेवा 30 वर्ष पूर्ण होने के कारण राज्य शासन एतद्वारा अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं) नियमावली, 1958 के नियम-16(2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निर्धारित तीन माह की कालावधि में छूट प्रदान कर अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने के पूर्व श्री धनंजय देवांगन, भा.प्र.से. (सीजी: 2004) को दिनांक 16-12-2022 (अपरान्ह) से सेवानिवृत्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

मछली पालन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 25 जुलाई 2022

क्रमांक/246/एफ-6-4/36/तकनीकी/2019.—विभागीय आदेश दिनांक 24-03-2003 एवं इसमें समय-समय पर संशोधन प्रतिस्थापित करते हुए प्रचलित मछली पालन नीति जारी की गई थी.

2. राज्य में मछली पालन के क्षेत्र में समग्र एवं उत्तरोत्तर विकास तथा मछुआरों के सभी वर्गों की भागीदारी व संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रचलित मछली पालन नीति वर्ष 2003 के स्थान पर राज्य शासन एतद्वारा राज्य की “नवीन मछली पालन नीति” जारी करता है.

छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन मछली पालन नीति

छत्तीसगढ़ राज्य गठन पश्चात् राज्य में मछलीपालन के विकास में वृद्धि हो रही है. राज्य में उपलब्ध जल संसाधन की दृष्टि से मछली पालन का एक विशिष्ट स्थान है. राज्य की भौगोलिक एवं कृषि जलवायुवीय परिस्थितियां मछलीपालन हेतु उपयुक्त होने से मछलीपालन कम लागत और कम समय में अधिक आय उपार्जन हेतु सहायक व्यवसाय के रूप में ग्रामीण अंचलों में अत्यन्त लोकप्रिय है. वर्तमान में राज्य मत्स्य बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर है एवं अन्य राज्यों को मत्स्य बीज का निर्यात कर रहा है तथा राज्य मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में देश में पांचवे स्थान पर एवं मत्स्योत्पादन के क्षेत्र में छठवें स्थान पर है तथा राज्य के 1.999 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र में से 98 प्रतिशत जलक्षेत्र में मछलीपालन हो रहा है.

राज्य गठन पश्चात् राज्य में मात्स्यिकी क्षेत्र के साथ-साथ राज्य के मछुआरों के आर्थिक, सामाजिक एवं वित्तीय परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं. मुख्य रूप से मत्स्य पालन, मत्स्य बीज उत्पादन, नवीन तकनीकों के विकास एवं उपयोग तथा नवीन प्रजातियों के पालन एवं विकास, अंतर्राज्यीय मत्स्य बीज/मत्स्य आयात-निर्यात में बदलाव परिलक्षित हुए हैं.

प्रदेश के मत्स्य पालकों के समग्र एवं उत्तरोत्तर विकास के लिए मछुआरों के सभी वर्गों की भागीदारी, संरक्षण, मत्स्य सहकारी समितियों के विकास, विभागीय योजनाओं/गतिविधियों के प्रचार-प्रसार, मात्स्यिकी तकनीक के उचित प्रशिक्षण, राज्य के प्रति हेक्टेयर मत्स्य एवं मत्स्य बीज के उत्पादन में वृद्धि, राज्य की मत्स्य निर्यात नीति, नवीन तकनीकों यथा आर.ए.एस., बायोप्लाक, केज कल्चर के विकास के साथ अनुसंधान एवं नवीन तकनीकों के परीक्षण एवं विकास के साथ ही नवीन प्रजातियों यथा जयंती रोहू आदि के पालन के साथ-साथ देशी मत्स्य प्रजातियों के संरक्षण एवं विकास के लिए नवीन मछुआ नीति लागू किया जाना आवश्यक है.

राज्य में मछली पालकों को कृषि के अनुरूप विद्युत दर, सिंचाई दर एवं संस्थागत ऋण उपलब्ध कराये जाने के साथ किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है.

प्रदेश में आनुवांशिक रूप से विकसित मत्स्य प्रजातियों के मत्स्य बीज उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है. नवीन मछलीपालन नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में उपलब्ध संपूर्ण जलक्षेत्र को मत्स्य पालन अंतर्गत लाते हुए मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि करना है साथ ही गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज उत्पादन एवं मत्स्य उत्पादन में प्रदेश को सशक्त बनाना है. इस हेतु प्रदेश में जैव विविधता एवं स्थानीय महत्वपूर्ण देशी प्रजातियों यथा देशी मांगूर, पाबदा एवं सांवल मछली इत्यादि का संरक्षण, प्रजनन एवं पालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा मत्स्य पालकों को आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकी का प्रत्यक्ष प्रदर्शन के लिए अन्य जिलों एवं राज्यों में क्रियान्वित नवीनतम तकनीकों का अध्ययन करने हेतु मत्स्य कृषकों को विभागीय योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण एवं उनके कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है. विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को भी केन्द्रीय अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से उन्नयन प्रशिक्षण दिए जाने का प्रस्ताव है. मत्स्य विपणन एवं मूल्य संवर्धन के लिए बुनियादी ढांचे को विकसित किये जाने के साथ सहकारिता के माध्यम से मत्स्य विपणन को बढ़ावा दिए जाने का प्रस्ताव है.

मछली की उत्पादकता वृद्धि हेतु तालाबों की मिट्टी, पानी के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणवत्ता को बनाये रखने एवं मछलियों की बिमारियों के रोकथाम के लिए अनुसंधान कार्य किये जाने हेतु मछली पालन नीति में प्रस्ताव है. प्रदेश में आलंकारिक मछलीपालन एवं गम्बुसिया मछलीपालन को भी प्रोत्साहित किया जाना है.

राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना अंतर्गत गोठानों को स्वालंबी बनाने एवं समितियों की आय में वृद्धि हेतु गोठान क्षेत्र स्थित तालाबों में मछली पालन कार्य से समितियों को जोड़ा जाना है. इसी प्रकार प्रदेश स्थित अनुपयोगी खाली पड़े खदानों में केज कल्चर के माध्यम से मछलीपालन को बढ़ावा दिया जाकर रोजगार सृजित किया जाना है. नक्सल प्रभावित क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा एवं कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए रिक्त तालाबों एवं जलाशयों में विभाग द्वारा निःशुल्क मछली बीज का संचयन किया जाएगा.

नवीन मछलीपालन नीति से प्रदेश में मत्स्य पालन को प्रोत्साहित किया जाएगा एवं राज्य को मत्स्य निर्यात के क्षेत्र में अग्रसर करने के साथ ही स्थानीय मछुआरों एवं मत्स्य कृषकों को रोजगार एवं उनके आर्थिक उन्नयन में सहायक सिद्ध होगा.

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विभाग के आदेश वर्ष 2003 द्वारा जारी एवं समय-समय पर संशोधित मछुआ नीति के स्थान पर नवीन मछली पालन नीति अंतर्गत निम्नानुसार बिन्दुओं को शामिल किया गया है :—

क्रमांक - 1 — त्रि-स्तरीय पंचायत व्यवस्था अंतर्गत तालाब/जलाशय को मछली पालन हेतु पट्टे पर देने/खुली निविदा आमंत्रित कर 10 वर्ष के लिए आबंटित करने के अधिकार निम्नानुसार रहेंगे :—

- 1.1 0-10 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र के तालाब/जलाशय-ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार 10 वर्षीय पट्टे पर प्रदान किये जायेंगे. तथा पंचायत राज व्यवस्था अंतर्गत 10 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र से अधिक के तालाबों/जलाशयों को मछली पालन के लिए खुली निविदा आमंत्रित कर 10 वर्ष के लिए आबंटित करने का अधिकार निम्नानुसार रहेंगे :—
- 1.2 10 हेक्टेयर से अधिक एवं 100 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र तक के तालाब/जलाशय-जनपद पंचायत.
- 1.3 100 हेक्टेयर से अधिक एवं 200 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र तक के तालाब/जलाशय-जिला पंचायत.
- 1.4 200 हेक्टेयर से अधिक एवं 1000 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र तक के जलाशय/बैराजों को मछलीपालन विभाग द्वारा मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को खुली निविदा आमंत्रित कर 10 वर्ष के लिए आबंटित किया जाएगा.
- 1.5 1000 हेक्टेयर से अधिक के जलाशय/बैराज मत्स्य पालन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य महासंघ के आधिपत्य में रहेंगे. मत्स्य महासंघ द्वारा उक्त जलाशयों को खुली निविदा आमंत्रित कर मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति, पंजीकृत व्यावसायिक संस्था/कंपनी/फर्म/समूह/व्यक्ति को 10 वर्ष के लिए आबंटित किया जाएगा. मत्स्य महासंघ द्वारा उक्त जलाशयों की खुली निविदा से प्राप्त आय का 50% रायल्टी राज्य शासन के खाते में जमा करेगी.
- 1.6 राज्य में प्रवाहित नदियों पर बने एनीकट्स एवं उन पर स्थित दह (Deep pool) जो 20 हेक्टेयर से अधिक के हो, को निर्धारित समयावधि के लिए मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति/महिला स्व. सहायता समूहों/मछुआ व्यक्ति को पट्टे पर दी जावेगी तथा पट्टे पर देने की कार्यवाही संचालक, मछली पालन के माध्यम से की जाएगी. इस हेतु एनीकट्स/दहों के आस-पास के ग्रामीण जो मत्स्याखेट से जीवन-यापन करते हैं, उन मछुआरों का नदी एवं दहवार सहकारी समिति का गठन कर पट्टे पर दिये जाने की कार्यवाही की जावेगी. नदियों एवं 20 हेक्टेयर से कम जलक्षेत्र वाले एनीकट/दहों में निःशुल्क मत्स्याखेट की व्यवस्था यथावत रहेगी.
- 1.7 नगरीय निकाय अंतर्गत आने वाले समस्त जलक्षेत्र नगरीय निकाय अंतर्गत रहेंगे. नगरीय क्षेत्रों तथा नगरीय निकायों के तालाबों/जलाशयों को शासन की नीति अनुसार खुली निविदा आमंत्रित कर 10 वर्ष के लिए आबंटित किया जावेगा.

क्रमांक - 2 — 0 से 10 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र के तालाब/जलाशय का पट्टा आबंटन करने हेतु प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगा :—

- 2.1 **मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति** (सामान्य क्षेत्र में ढीमर, निषाद, केंवट, कहार, कहरा, मल्लाह के मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को प्राथमिकता एवं अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को प्राथमिकता होगी).
- 2.2 **स्थानीय महिला स्व सहायता समूह** (सामान्य क्षेत्र में ढीमर, निषाद, केंवट, कहार, कहरा, मल्लाह के स्व सहायता समूहों को प्राथमिकता एवं अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्व सहायता समूह व छ.ग. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्व सहायता समूह को प्राथमिकता होगी).
- 2.3 **मछुआ व्यक्ति/मत्स्य कृषक** — ऐसे मछुआ व्यक्ति/बेरोजगार युवा जो मछली पालन में डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर हो.

- 2.4 ऐसे क्षेत्र जहां वर्ष 1965 या उसके पश्चात् मकान, भूमि आदि डूब में आने के कारण कोई परिवार विस्थापित हो गये हो, ऐसे व्यक्तियों/परिवारों या उनके समूह एवं समिति को संबंधित जलक्षेत्र में पट्टे पर दिये जाने हेतु प्राथमिकता रहेगी.
- 2.5 गोधन न्याय योजना अन्तर्गत निर्मित गौठान हेतु निर्मित तालाबों में मछली पालन का कार्य गौठान समिति या उनके द्वारा चिन्हित समूह द्वारा की जावेगी.
- 2.6 10 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र से उपर के समस्त तालाबों/जलाशयों को खुली निविदा के आधार पर आबंटित किये जावेंगे. किन्तु प्राथमिकता बिन्दु क्र. 2.1 में वर्णितानुसार होगा.
- 2.7 योजनाओं में चयनित हितग्राही की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए.
- 2.8 निविदा में समान दर प्राप्त होने पर सामान्य क्षेत्र में ढीमर, निषाद, केंवट, कहार, कहरा, मल्लाह के मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को एवं अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समितियों को प्राथमिकता होगी तथा अधिकतम निविदा दर प्राप्त होने पर उक्त मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को 10 प्रतिशत छुट की पात्रता होगी.

“मछुआ” से तात्पर्य :—

“मछुआ” से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो अपनी आजीविका का अर्जन मछलीपालन, मछली पकड़ने या मछली बीज उत्पादन आदि कार्य करता है.

क्रमांक - 3— त्रिस्तरीय पंचायत के तालाबों/जलाशयों के पट्टा आबंटन की प्रक्रिया :—

- 3.1 **बिन्दु क्रमांक-2** में वर्णित प्राथमिकता क्रम में तालाब/जलाशय का आबंटन स्थानीय मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति, महिला स्व सहायता समूह, मछुआ व्यक्ति को आबंटित किया जावेगा. स्थानीय मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति, महिला स्व सहायता समूह, मछुआ व्यक्ति उपलब्ध न होने की दशा में समीपस्थ मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति, महिला स्व सहायता समूह अथवा मछुआ व्यक्ति को निर्धारित नीति अनुसार आबंटित किया जावेगा.
- 3.2 मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति अथवा मछुआ व्यक्ति को ग्रामीण तालाब के मामले में अधिकतम 1.00 हेक्टेयर तथा सिंचाई जलाशय के मामले में 4.00 हेक्टेयर प्रति सदस्य/व्यक्ति के मान से आबंटित किया जावेगा.
- 3.3 मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को एक से अधिक तालाब ऊपर वर्णित अधिकतम औसत जलक्षेत्र सीमा तक निर्धारित नीति अनुसार आबंटित किया जा सकता है.

क्रमांक - 4— तालाबों/सिंचाई जलाशयों में लीज की समय सीमा 10 वर्ष तथा लीज अवधि समाप्त होने की तिथि 15 जून होगी.

क्रमांक - 5— पंचायतों के द्वारा लीज राशि में बढ़ोतरी प्रति 02 वर्ष में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर निर्धारण किया जावेगा. जिससे पंचायतों की आय में वृद्धि हो एवं उक्त राशि से ग्रामीणों के जन हितार्थ कार्यों से विकास किया जा सके.

क्रमांक - 6— 10 वर्षीय पट्टा आबंटन/निविदा अवधि समाप्त होने पर यदि उस व्यक्ति, समूह व समिति का सम्पूर्ण रिकार्ड अच्छा रहा हो तो उस व्यक्ति, समूह व समिति को पुनः निविदा से आबंटन दिए जाने के लिए प्रथम प्राथमिकता होगी. निविदा दर समान होने पर (सामान्य क्षेत्र में ढीमर, निषाद, केंवट, कहार, कहरा, मल्लाह के मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को प्राथमिकता एवं अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समितियों को प्राथमिकता होगी. यह प्रक्रिया पट्टा अवधि समाप्त होने के 06 माह पहले ही कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी.

क्रमांक - 7 — तालाब/जलाशय की क्षमता को देखते हुए एक से अधिक मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समितियों का गठन किया जा सकेगा। आदिवासी मछुआ सहकारी समिति में गैर आदिवासी सदस्यों का प्रतिशत 33 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत होगा, साथ ही अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्र में आवश्यक रूप से मछुआ सहकारी समिति के अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहेगा। लेकिन समिति के उपाध्यक्ष पद हेतु मछुआ जाति (ढीमर, निषाद, केंवट, कहार, कहरा, मल्लाह) के सदस्यों को प्राथमिकता रहेगी।

मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति का कार्यक्षेत्र उनके बायलॉज में वर्णित ग्रामों की परिधि तक रहेगा। समिति के बायलॉज में वर्णित प्रत्येक ग्रामों में समिति के कम से कम 05 सदस्य अथवा जलक्षेत्र के अनुपात में सदस्य होना आवश्यक होगा। ऐसी पुरानी समिति जिनके बायलॉज में ग्राम दर्ज नहीं है, उक्त समितियों का परिसीमन कराया जावेगा।

यदि तालाबों/जलाशयों के परिधि क्षेत्र में जलक्षेत्र की उपलब्धता के आधार पर नवीन मछुआ समूह एवं नवीन पंजीकृत समिति का गठन आवश्यक हो तो ऐसी स्थिति में नवीन मछुआ समूह एवं समिति के गठन/पंजीयन हेतु सामान्य क्षेत्र में 75% सदस्य ढीमर, निषाद, केंवट, कहार, कहरा, मल्लाह संवर्ग के होंगे तथा मछली पालन विभाग की अनुशंसा एवं पूर्व में पंजीकृत मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति का ठहराव प्रस्ताव एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा। पूर्व पंजीकृत मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति द्वारा 30 दिवस में अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुशंसा नहीं दिए जाने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही हेतु विभाग स्वतंत्र होगा। समिति पंजीयन में आर्थिक वायोबिलिटी को दृष्टिगत रखते हुए मछली पालन विभाग की अनुशंसा एवं तकनीकी प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात् ही सहकारिता विभाग द्वारा पंजीयन कार्यवाही की जावेगी।

क्रमांक - 8 — ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायतों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के तालाबों/जलाशय को मछलीपालन नीति अनुरूप तीन माह के भीतर आबंटन/निविदा कार्यवाही नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित पंचायत की अनुशंसा/सहमति लिए बिना नियमानुसार तालाब/जलाशय आबंटन/निविदा करने का अधिकार मछलीपालन विभाग के माध्यम से संबंधित विहित प्राधिकारी (जिले के कलेक्टर) को होगा तथा उक्त तालाब जलाशय आबंटन/निविदा में प्राप्त राशि संबंधित पंचायत के कोष में जमा की जावेगी।

क्रमांक - 9 — प्रत्येक ग्राम में आवश्यकतानुसार निस्तार हेतु तालाब चिन्हांकित किया जावेगा।

निस्तारी तालाबों के चिन्हांकन के संबंध में ग्रामीणों को निस्तार में होने वाली असुविधाओं को ध्यान में रखकर प्रत्येक ग्राम में आवश्यकतानुसार निस्तार हेतु तालाब चिन्हांकित किया जावेगा। चिन्हांकन संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा या उनके प्रतिनिधि जो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से कम से स्तर के न हो, के द्वारा किया जावेगा। उक्त चिन्हांकित निस्तारी तालाब में मत्स्य पालन का कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही अवैधानित रूप से मत्स्य पालन कार्य किये जाने की स्थिति में पंचायत अधिनियम के तहत विहित प्राधिकारी (जिले के कलेक्टर) द्वारा नीति के उल्लंघन करने वाले संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

क्रमांक - 10 — मत्स्य महासंघ को जलाशय निविदा से प्राप्त कुल राशि का 50% मछली पालन विभाग के राजस्व खाते में देय होगा तथा शेष 50% में से 25% राशि का उपयोग स्थानीय स्तर पर मत्स्याखेट करने वाले मछुआओं को उत्पादकता बोनस के रूप में देय होगा।

क्रमांक - 11 — मछली बीज की गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रमाणीकरण।

मछली बीज का गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रमाणीकरण मत्स्य पालन हेतु मत्स्य बीज सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है, स्वस्थ और उन्नत प्रजाति के मत्स्य बीज का उत्पादन कर मत्स्योत्पादन बढ़ाने हेतु मछली बीज की गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रमाणीकरण हेतु राज्य में मत्स्य बीज प्रमाणीकरण अधिनियम बनाया जाएगा। मत्स्यबीज उत्पादन हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगा एवं इसके लिए विभाग निजी व्यक्तियों को मत्स्य बीज उत्पादन संबंधी तकनीकी से अवगत करायेंगा एवं समय-समय पर मार्गदर्शन देगा। राज्य शासन द्वारा प्रतिबंधित प्रजाति के मछली का मत्स्यबीज उत्पादन/पालन/परिवहन/विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मत्स्य बीज विक्रय करने वालों एवं उत्पादकों को कृषि (मछली पालन) विभाग में पंजीयन कराना एवं विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। निजी क्षेत्र में अधिक से अधिक हैचरी एवं संवर्धन प्रक्षेत्रों का निर्माण को प्रोत्साहित किया जावेगा एवं शासन की नीति अनुरूप अनुदान उपलब्ध कराया जावेगा।

क्रमांक - 12— विभाग में मत्स्य निरीक्षक की भूमिका मत्स्य पालन कार्यों में विकास एवं विस्तार अधिकारी के रूप में होगी तथा वे जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करेंगे।

क्रमांक - 13— विभाग सिंचाई जलाशयों में केज कल्चर योजना क्रियान्वयन हेतु पूर्ण रूप से अधिकृत होगा। इस हेतु सिंचाई जलाशय को दीर्घ अवधि के लिए केज कल्चर हेतु लीज पर देगा। राज्य में उपलब्ध 50 हेक्टेयर से अधिक जलक्षेत्र के जलाशय जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य महासंघ/मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समितियों/महिला स्व सहायता समूह/व्यक्ति/पंजीकृत व्यावसायिक संस्था/कंपनी/फर्म को दीर्घावधि के लिए मछली पालन हेतु आबंटित किये गये हैं, उन जलाशय में केज कल्चर के माध्यम से मछली पालन के लिए केज स्थापित करने हेतु जलक्षेत्र आबंटन कर दिया जाएगा। इस हेतु जलाशयों के कुल जलभराव क्षेत्रफल (Total Water Spread Area) का अधिकतम पांच प्रतिशत जलक्षेत्र केज/पैन स्थापना एवं संचालन तथा मत्स्य अनुसंधान कार्यों हेतु आरक्षित रहेगा।

केज कल्चर की पट्टा अवधि 10 वर्ष होगी। केज में मछलीपालन कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता न होने की स्थिति में पट्टा अवधि पुनः 05 वर्ष बढ़ाया जा सकेगा।

विभागीय एवं अन्य योजना के अंतर्गत जलाशयों में विभाग द्वारा स्थापित केज की लीज राशि 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष होगी तथा हितग्राही द्वारा योजनाओं में स्थापित केज की लीज राशि 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष होगी, जिसमें प्रत्येक 02 वर्षों में 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि किया जावेगा। उक्त लीज राशि संबंधित जिले के मछलीपालन विभाग के विभागीय राजस्व मद में जमा होगी।

क्रमांक - 14— राज्य के खदानों में मछली पालन को बढ़ावा दिया जावेगा।

राज्य स्थित खनिज विभाग/पंचायत विभाग के अनुपयोगी एवं खाली पड़े खदानों को मछलीपालन हेतु उपयोग में लाया जावेगा। खदानों को नियमानुसार स्थानीय बेरोजगारों को पट्टे पर प्रदाय किया जावेगा एवं बड़े खदानों में मछलीपालन को बढ़ावा देने हेतु केज स्थापना हेतु प्रयास किया जावेगा।

क्रमांक - 15— नक्सल प्रभावित क्षेत्रों/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा एवं कुपोषण की समस्या को दूर करने हेतु मछली पालन को बढ़ावा दिया जावेगा।

मछली आहार प्रोटीन का उपयुक्त साधन है अतः उक्त क्षेत्र के तालाबों/जलाशयों में मछली पालन विभाग द्वारा निःशुल्क मछली बीज का संचयन किया जावेगा एवं अधिक से अधिक लोगों को मछली पालन के माध्यम से स्वरोजगार से जोड़ा जावेगा।

(तुलिका प्रजापति)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन मछली पालन विभाग

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 नवम्बर 2022

क्रमांक/340/एफ-6-4/36/तकनीकी/2019.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 25-07-2022 द्वारा जारी “नवीन मछली पालन नीति” में मछुआरों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन एतद्वारा जारी नीति के निम्न कंडिका/बिन्दुओं में निम्नानुसार संशोधन प्रतिस्थापित करता है।

बिन्दु क्रमांक-1— त्रि-स्तरीय पंचायत व्यवस्था अंतर्गत तालाब/जलाशय को मछली पालन हेतु 10 वर्ष के लिए पट्टे पर आबंटित करने के अधिकार निम्नानुसार रहेंगे :—

1.1. 0-10 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र के तालाब/जलाशय - ग्राम पंचायत

- 1.2. 10 हेक्टेयर से अधिक एवं 100 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र तक के तालाब/जलाशय – जनपद पंचायत.
- 1.3. 100 हेक्टेयर से अधिक एवं 200 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र तक के तालाब/जलाशय – जिला पंचायत.
- 1.4. 200 हेक्टेयर से अधिक एवं 1000 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र तक के जलाशय/बैराजों को मछलीपालन विभाग द्वारा मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को पट्टे पर आबंटित किया जावेगा.
- 1.7. नगरीय निकाय अंतर्गत आने वाले समस्त जलक्षेत्र नगरीय निकाय अंतर्गत रहेंगे. नगरीय क्षेत्रों तथा नगरीय निकायों के तालाबों/जलाशयों को शासन की नीति अनुसार 10 वर्ष के लिए आबंटित किया जाएगा.

बिन्दु क्रमांक-2— तालाब/जलाशय का पट्टा आबंटन करने हेतु प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगा :—

- 2.1. मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति (सामान्य क्षेत्र में ढीमर, निषाद, केंवट, कहार, कहरा, मल्लाह के मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को प्राथमिकता एवं अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति) को प्राथमिकता होगी.
- 2.6. विलोपित.

“मछुआ” से तात्पर्य :— “मछुआ” से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो अपनी आजीविका का अर्जन मछलीपालन, मछली पकड़ने या मछली बीज उत्पादन आदि कार्य करता हो. [“वंशानुगत/परंपरागत मछुआ समुदाय धीवर (ढीमर), निषाद (केंवट), कहार, कहरा, मल्लाह को प्राथमिकता दी जावेगी.”]

बिन्दु क्रमांक-3— त्रिस्तरीय पंचायत के तालाबों/जलाशयों के पट्टा आबंटन प्रक्रिया.

- 3.2. मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति अथवा मछुआ व्यक्ति को ग्रामीण तालाब के मामले में अधिकतम 1.0 हेक्टेयर के स्थान पर 0.50 हेक्टेयर तथा सिंचाई जलाशय के मामले में 4.0 हेक्टेयर के स्थान पर 2.00 हेक्टेयर प्रति सदस्य/व्यक्ति के मान से आबंटित किया जाए.

अतिरिक्त बिन्दु :— बिन्दु क्रमांक-7 के पैरा-4 में “मछली पालन के लिए गठित समितियों का मूल्यांकन सहकारिता विभाग एवं मछली पालन विभाग के संयुक्त टीम द्वारा किया जाएगा एवं समितियों के दायित्व एवं वस्तुस्थिति के अनुसार समितियों को परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी एवं नवीन समितियों के गठन किया जा सकेगा.” जोड़ा जाए.

“नवीन मछली पालन नीति” की शेष कंडिकाएं/बिन्दु यथावत रहेगी.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 दिसम्बर 2022

क्रमांक/354/एफ-6-4/36/तकनीकी/2019.— “नवीन मछली पालन नीति” की विभिन्न कंडिका/बिन्दुओं में संशोधन करते हुए विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक/340/एफ 6-4/36/तकनीकी/2019, दिनांक 21-11-2022 में राज्य शासन एतद्वारा जहां-जहां “मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति” अंकित है, उसके स्थान पर “मत्स्य सहकारी समिति एवं मछुआ समूह” प्रतिस्थापित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तुलिका प्रजापति, उप सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 जनवरी 2023

क्रमांक एफ 10-6/2017/16.—असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-6/2017/16, दिनांक 09-12-2019 में असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना की कण्डिका (घ) में निम्नानुसार संशोधन अंतः स्थापित करती है :—

(घ) **योजना हेतु पात्रता :—**

06. योजना का लाभ लेने हेतु असंगठित कर्मकार का मंडल में पंजीयन मृत्यु के कम से कम 90 दिवस पूर्व होना अनिवार्य है.

उपरोक्त संशोधन अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश साहू, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 दिसम्बर 2022

क्रमांक एफ 3-73/2022/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (घ) के अनुसरण में राज्य सरकार, एतद्वारा, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट स्थान को, उसके तत्स्थानी कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए, यातायात अपराधों के संबंध में, “पुलिस थाना” घोषित करती हैं :—

अनुसूची

स. क्र. (1)	पुलिस थाना का नाम (2)	संबंधित पुलिस थाने के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्र (3)
1.	यातायात पुलिस थाना, दुर्ग	दुर्ग, मोहन नगर, पुलगांव, धमधा, बोरी, अण्डा
2.	यातायात पुलिस थाना, आकाश गंगा	सुपेला, वैशाली नगर, जामुल, खुर्सीपार, छावनी
3.	यातायात पुलिस थाना, सिविक सेंटर	भिलाई नगर, भिलाई भट्टी, नेवई, पाटन, रानीतराई, उतई जामगांव (आर)
4.	यातायात पुलिस थाना, पुरानी भिलाई- चरोदा	पुरानी भिलाई, कुम्हारी, अम्लेश्वर, नंदनी

No. F-3-73/2022/Home-2.—In pursuance of clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the State Government, hereby, with effect the date of publication of this notification in the official Gazette, the place specified in column (2) of the schedule below, declares as “Police Station” for the areas specified

in the corresponding column (3) thereof, in respect of traffic offences :—

SCHEDULE

S. No.	Name of Police Station	Areas falling within the Respective Jurisdiction of the Police Station
(1)	(2)	(3)
1.	Traffic Police Station, Durg	Durg, Mohan Nagar, Pulgaon, Dhamdha, Bori, Anda
2.	Traffic Police Station, Aakash Ganga	Supela, Vaishali Nagar, Jamul, Khursipar, Chhawani
3.	Traffic Police Station Civic Center	Bhilai Nagar, Bhilai Bhatti, Newai, Patan, Ranitarai, Utai, Jamgaon (R)
4.	Traffic Police Station, Purani Bhilai-Charoda.	Purani Bhilai, Kumhari, Amleashwar, Nandni

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 जनवरी 2023

क्रमांक एफ 3-72/2022/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (ध) के अनुसरण में राज्य सरकार, जनसुविधा तथा प्रशासनिक कारणों की दृष्टि से, एतद्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधित करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित पुलिस थाना, जिसकी प्रविष्टियां तत्स्थानी कॉलम (4) तथा (5) में उल्लिखित हैं, को कॉलम (2) में उल्लिखित पुलिस थाना/चौकी के स्थानीय क्षेत्राधिकार के रूप में अधिसूचित करती है :—

सारणी

स. क्र.	उस पुलिस थाना/तहसील एवं जिला का नाम, जिसमें सम्मिलित किया जाना है	उस पुलिस थाना/तहसील एवं जिला का नाम, जिसमें अपवर्जित किया जाना है	प्रस्तावित ग्रामों के नाम	पटवारी हल्का नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	पुलिस थाना - इंदागांव तहसील-मैनपुर जिला-गरियाबंद	पुलिस थाना - अमलीपदर तहसील-मैनपुर जिला-गरियाबंद	ग्राम-धुरवागुड़ी	14

No. F-3-72/2022/Home-2.—In pursuance of clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the State Government, in view of Public Convenience and Administrative reasons, hereby, by making partial amendment in the previous notification issued in this behalf the Police station mentioned in column (3) having corresponding entries mentioned in column (4) and (5), notifies as local jurisdiction of Police Station/Out Post mentioned in column (2) in the Table below :—

TABLE

S. No.	Name of that Police Station/Tahsil and District in which to be included	Name of that Police Station/Tahsil/District out of which to be excluded	Name of the Proposed village	Patwari Halka Number
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Police Station - Indagav Tahsil - Mainpur District - Gariyaband	Police Station - Amlipadar Tahsil - Mainpur District - Gariyaband	Village - Durvagudi	14

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 जनवरी 2023

क्रमांक एफ 3-74/2022/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (घ) के अनुसरण में, राज्य सरकार, जनसुविधा तथा प्रशासनिक कारणों की दृष्टि में, एतद्वारा, इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचना में आंशिक संशोधित करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लेखित पुलिस थाना, जिसकी प्रविष्टियां तत्स्थानी कॉलम (4) तथा (5) में उल्लेखित हैं, को कॉलम (2) में उल्लेखित पुलिस थाना/चौकी के स्थानीय क्षेत्राधिकार के रूप में अधिसूचित करती है :—

सारणी

स. क्र.	उस पुलिस थाना/चौकी का नाम, तहसील एवं जिला जिसमें सम्मिलित किया जाना है.	उस पुलिस थाना/चौकी का नाम, तहसील एवं जिला जिससे अपवर्जित किया जाना है.	शामिल होने वाले प्रस्तावित ग्रामों के नाम	पटवारी हल्का नम्बर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जिला दुर्ग				
01	चौकी गाड़ाडीह थाना-उतई तहसील- पाटन जिला-दुर्ग	पुलिस थाना-उतई तहसील- पाटन जिला- दुर्ग	गाड़ाडीह	29
02			परसाही	28
03			फेकारी	28
04			बोहारडीह	19
05			आमालोरी	32
06			बोदल	29
07			मटंग	19
08			मानिकचौरी	19
09			मर्रा	32
10		चौकी-मचान्दुर थाना-उतई तहसील- पाटन जिला-दुर्ग	कानाकोट	30
11		थाना-उतई तहसील- पाटन जिला- दुर्ग	सोरम	34
12			धुमा	34
13			सांतरा	22
14			नगपुरा	2
15	चौकी नगपुरा तहसील- दुर्ग जिला-दुर्ग	पुलिस थाना-पुलगांव तहसील- दुर्ग जिला- दुर्ग	खुरसुल	4
16			खुर्सीडीह	3
17			भेड़सर	10
18			बोरई	3
19			दमोदा	3
20	थाना-पद्मनाभपुर तहसील- दुर्ग जिला- दुर्ग	थाना- दुर्ग चौकी- पद्मनाभपुर तहसील- दुर्ग जिला- दुर्ग	पद्मनाभपुर	56/25 अ
21			कसारीडीह	56/25 अ
22			कन्हैयापुरी	56/25 अ
23			सुभाष नगर	56/25 अ
24			आदर्श नगर	56/25 अ
25			मुक्त नगर	56/25 अ
26			फोकटपारा	56/25 अ

27			केलाबाड़ी	56 / 25 अ
28			नई पुलिस लाइन	52 / 20 अ
29			पांच बिल्डिंग	52 / 25 अ
30			ठगड़ा बांध बस्ती	52 / 25 अ
31			रायपुर नाका	52 / 20 अ
32			उडिया कालोनी	52 / 20 अ
33			सिंधी कालोनी	52 / 20 अ
34			पोटिया रोड	55 / 23 अ
35			कुंदरा पारा	55 / 23 अ
36			इंदिरा कालोनी	55 / 23 अ
37			देवारपारा	56 / 25 अ
38			बस स्टैण्ड	56 / 25 अ
39			पालिटेक्निक कालेज	56 / 25 अ
40			बी.आई.टी. कालेज	56 / 25 अ
41	थाना-पद्मनाभपुर तहसील- दुर्ग जिला- दुर्ग	थाना- पुलगांव तहसील- दुर्ग जिला- दुर्ग	बोरसी वार्ड क. 45,50,51,52 के अंतर्गत (बोरसी कालोनी, वृन्दानगर, विद्युत नगर, रजनीगंधा कालोनी, हा. बोर्ड बोरसी, पंचशील सेक्टर, पैराडाईज कालोनी, बोरसीभाठा, विराट नगर, मधुवन नगर, सुन्दर नगर, प्रदिप्ती नगर, गणपति विहार)	23
42	थाना-पद्मनाभपुर तहसील- दुर्ग जिला- दुर्ग	थाना- पुलगांव तहसील- दुर्ग जिला- दुर्ग	पोटियाकला वार्ड क. 53,54 के अंतर्गत (न्यू आदर्श नगर, विवेकानंद नगर, मिनाक्षी नगर, अटल आवास)	23-अ

No. F 3-74/2022/Home-II.—In pursuance of clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the State Government, in view of Public Convenience and Administrative reasons, hereby, by making partial amendment in the previous notifications issued in this behalf, the Police station mentioned in column (3) having corresponding entries mentioned in column (4) and (5) , notifies as local jurisdiction of Police Station/Out Post mentioned in column (2) in the Table below :—

TABLE

S. N.	Name of that Police Station/Tahsil and District in which to be included	Name of that Police station/ Tehsil/District out of which to be excluded	Name of the proposed villages	Patwari Halka Number
1	2	3	4	5
1	Out Post- Gadadih Police Station- Utai Tahsil- Patan District- Durg	Police Station- Utai Tahsil- Patan District- Durg	Gadadih	29
2			Parsahi	28
3			Fekari	28
4			Bohardih	19
5			Aamalori	32
6			Bodal	29
7			Matang	19
8			Manikchori	19
9			Marra	32
10		Out Post- Machandur Police Station- Utai Tahsil- Patan District- Durg	Kanakot	30
11	Out Post- Nagpura Tahsil- Durg District- Durg	Police Station- Utai Tahsil- Patan District- Durg	Soram	34
12			Ghuma	34
13			Saantra	22
14			Nagpura	2
15	Out Post- Nagpura Tahsil- Durg District- Durg	Police Station- Pulgaon Tahsil- Durg District- Durg	Khursul	4
16			Khursidih	3
17			Bhendsar	10
18			Borai	3
19			Damoda	3
20	Police Station- Padamanabhpur Tahsil- Durg District- Durg	Police Station- Durg Out Post- Padamanabhpur Tahsil- Durg District- Durg	Padamanabhpur	56/25 A
21			Kasaridih	56/25 A
22			Kanhaiyapuri	56/25 A
23			Subhash Nagar	56/25 A
24			Aadarsh Nagar	56/25 A
25			Mukt Nagar	56/25 A
26			Fokatpara	56/25 A
27			Kelabadi	56/25 vA

28			Nayi Police Line	52/20 A
29			Panch Building	52/25 A
30			Thagda Bandh Basti	52/25 A
31			Raipur Naka	52/20 A
32			Odiya Colony	52/20 A
33			Sindhi Colony	52/20 A
34			Potiya Road	55/23 A
35			Kundra Para	55/23 A
36			Indira Colony	55/23 A
37			Devarpara	56/25 A
38			Bus Stand	56/25 A
39			Pollytechnic Collage	56/25 A
40			B.I.T. Collage	56/25 A
41	Police Station- Padamanabhpur Tahsil- Durg District- Durg	Police Station- Pulgaon Tahsil- Durg District- Durg	Borsi Ward No. 45, 50, 51, 52 under the (Borsi Colony, Vrinda Nagar, Vidyut Nagar, Rajnigandha Colony, Housin Bord Borsi, Panchsheel Sector, Pairadaise Colony, Borsi Bhata, Virat Nagar, Madhuban Nagar, Sunder Nagar, Pradipti Nagar, Ganpati Vihar)	23
42			Potiyakala Ward No. 53,54 under the (New Aadarsh Nagar, Vivekanand Nagra, Minakshi Nagar, Atal Aawas)	23-A

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. कौशल, उप सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुन्द, दिनांक 20 दिसम्बर 2022

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/774/क/कले./भू-अर्जन/2021-22.— भूमि-अर्जन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है अर्थात् :-

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुन्द	पिथौरा	सानटेमरी प.ह.नं. 44	0.82 हे.	लोवर जोंक बैराज योजना के अन्तर्गत सानटेमरी शाखा नहर निर्माण कार्य हेतु.

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 29-12-2022 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत सानटेमरी तहसील पिथौरा में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि भू-अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	लोवर जोंक बैराज योजना से खरीफ फसल सिंचाई सुविधा के लिए शाखा नहर निर्माण कार्य हेतु.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	14
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	20
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
8.	लोवर जोंक बैराज योजना की कुल लागत	—	रु. 14068.43 लाख
9.	लोवर जोंक बैराज योजना से होने वाला लाभ	—	लोवर जोंक बैराज योजना से 1980 हेक्टेयर में खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात के लिये उपाय एवं उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये प्रयास तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय राशि 14068.43 लाख किये जा रहे हैं.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि भू-अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुन्द, दिनांक 20 दिसम्बर 2022

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/777/क/कले./भू-अर्जन/2021-22.—भूमि-अर्जन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित हे अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुन्द	पिथौरा	उतेकेल प.ह.नं. 45	2.52 हे.	लोवर जोंक बैराज योजना के अन्तर्गत उतेकेल माईनर निर्माण कार्य हेतु.

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 30-12-2022 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत उतेकेल तहसील पिथौरा में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	लोवर जोंक बैराज योजना से खरीफ फसल सिंचाई सुविधा के लिए शाखा नहर निर्माण कार्य हेतु.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	23
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	46
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
8.	लोवर जोंक बैराज योजना की कुल लागत	—	रु. 14068.43 लाख
9.	लोवर जोंक बैराज योजना से होने वाला लाभ	—	लोवर जोंक बैराज योजना से 1980 हेक्टेयर में खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात के लिये उपाय एवं उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये प्रयास तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय राशि 14068.43 लाख किये जा रहे हैं.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि भू-अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलेश कुमार क्षीरसागर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सुकमा, दिनांक 28 दिसम्बर 2022

क्रमांक/2766/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सुकमा	छिन्दगढ़	टहकवाड़ा प.ह.नं.-23	1.241	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सुकमा.	उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निर्धारण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सुकमा के कार्यालय में किया जा सकता है.

सुकमा, दिनांक 28 दिसम्बर 2022

क्रमांक/2767/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सुकमा	छिन्दगढ़	सगुनघाट प.ह.नं.-13/पालेम	0.915	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सुकमा.	उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निर्धारण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सुकमा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरीस. एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कबीरधाम, दिनांक 20 दिसम्बर 2022

राजस्व प्रकरण क्रमांक 273/202211080200013/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	बोड़ला	मड़मड़ा प.ह.नं.-11	0.101 में स्थित नलकूप	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.).	घोघरा व्यपवर्तन नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कवर्धा जिला कबीरधाम (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जनमेजय महोबे, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सूरजपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2022

क्रमांक/2230/भू-अर्जन/04/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला-सूरजपुर
(ख) तहसील-प्रेमनगर
(ग) नगर/ग्राम-प्रेमनगर, प.ह.नं. 13
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.3359 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (वर्गमीटर में)
(1)	(2)
3129	28
3028/4	8
3029/2	12

(1)	(2)	(1)	(2)
3055/4	6	2958	156
3114	29	3103/1	50
2960	72	904	27
2957/3	20	871	60
2611/4	12	913	42
907	132	862/2	48
912	12	861/1	06
863/2	30	810	28
862/1	60	120	48
99	108	799	14
808	32	774/2	18
115	10	773	460
797	32	2611/1	24
126	15	3029/1	12
13/7	10	3127	28
3028/3	24	3055/2	6
3128/2	12	3057	25
3029/4	8	3112	160
3121/1	20	2956	60
3071/1	30	2954/1	60
3109/2	20	906	68
3102/2	56	874	120
3075	20	863/1	42
876	48	914/2	36
873	30	861/5	32
914/1	36	100	32
915	32	803	25
811	16	798	32
113	44	138/1	504
800	06	13/8	12
774/1	04	योग	0.3359
3221/135	04	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तारा-प्रेमनगर-रामानुजनगर मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयनीकरण कार्य हेतु.	
13/6	12	(3) भूमि का नक्शा (प्लान), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है.	
3128/1	12	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
3029/3	8	इप्पकत आरा कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	
3030	14		
3121/3	20		
3113	20		

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

बेमेतरा, दिनांक 15 दिसम्बर 2022

क्रमांक 1182/भू-अभि./अ.भू.अ./2022.—नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल का सृजन, रा.नि.मं. के पटवारी हल्कों का समायोजन एवं पुनः क्रमांकन छ.ग. भू-राजस्व की धारा 104 एवं 105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं जितेन्द्र शुक्ला, कलेक्टर, बेमेतरा एतद्वारा जिला बेमेतरा अन्तर्गत नवीन तहसील देवकर में नवीन रा.नि.मं. गाड़ाडीह का पुनर्गठन एवं तहसील साजा, देवकर के पटवारी हल्कों का पुनः क्रमांकन निम्नांकित अनुसूची में दर्शित अनुसार करता हूँ :-

हल्का बंदी 2022-23 तहसील साजा जिला - बेमेतरा																	
क्र.	तहसील का नाम	वर्तमान				प्रस्तावित				खाता क्षेत्रफल	गैर खाता क्षेत्रफल	योग क्षेत्रफल	विरान/दुबान/माड़				
		रा.नि.म.	मुख्यालय का नाम	आबाद ग्राम	वर्तमान प.ह.नं.	रा.नि.म.	मुख्यालय का नाम	आबाद ग्राम	प्रस्तावित प.ह.नं.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
तहसील साजा रा.नि.मं. - साजा नगरीय जिला - बेमेतरा																	
1	साजा	साजा नगरीय	बरागड़ा	जाला	2	साजा नगरीय	बरागड़ा	जाला	2	258.05	28.85	286.90					
2	साजा	साजा नगरीय		धीरुपाडा		साजा नगरीय		धीरुपाडा		347.82	28.52	376.34					
3	साजा	साजा नगरीय		बरागड़ा		साजा नगरीय		बरागड़ा		288.07	60.26	348.33					
4	साजा	साजा नगरीय		मुसवाडीह		साजा नगरीय		मुसवाडीह		237.30	30.71	268.01					
5	साजा	साजा नगरीय		सोमईखुर्द		साजा नगरीय		सोमईखुर्द		450.80	39.87	490.67					
6	साजा	साजा नगरीय	बोड	काजरा	3	साजा नगरीय	बोड	काजरा	3	340.52	23.5	364.02					
7	साजा	साजा नगरीय		काहरी		साजा नगरीय		काहरी		175.21	34.26	209.47					
8	साजा	साजा नगरीय		खीतलई		साजा नगरीय		खीतलई		354.56	55.09	409.65					
9	साजा	साजा नगरीय		बोड		साजा नगरीय		बोड		300.29	51.2	351.49					
10	साजा	साजा नगरीय		रैगा		साजा नगरीय		रैगा		151.51	23.14	174.65					
11	साजा	साजा नगरीय	साजा	साजा	9	साजा नगरीय	साजा	साजा	9	973.69	114.08	1087.75					
योग										3712.82	499.46	4212.28					
तहसील साजा रा.नि.मं. - साजा ग्रामीण जिला - बेमेतरा																	
12	साजा	साजा ग्रामीण	घोटवाणी	कैलास	4	साजा ग्रामीण	घोटवाणी	कैलास	4	311.80	64.37	376.17					
13	साजा	साजा ग्रामीण		तैदुपाडा		साजा ग्रामीण		तैदुपाडा		232.16	24.73	256.89					
14	साजा	साजा ग्रामीण		खामडीह		साजा ग्रामीण		खामडीह		111.93	20.99	132.92					
15	साजा	साजा ग्रामीण		घोटवाणी		साजा ग्रामीण		घोटवाणी		567.32	112.62	679.94					
16	साजा	साजा ग्रामीण		रान्डी		साजा ग्रामीण		रान्डी		237.64	28.27	265.91					
17	साजा	साजा ग्रामीण	गडुवा	गडुवा	5	साजा ग्रामीण	गडुवा	गडुवा	5	324.96	46.32	371.28					
18	साजा	साजा ग्रामीण		गुडवा		साजा ग्रामीण		गुडवा		340.61	23.73	364.34					
19	साजा	साजा ग्रामीण		महीचही		साजा ग्रामीण		महीचही		377.70	52.11	429.81					
20	साजा	साजा ग्रामीण		तैदुपाडा		साजा ग्रामीण		तैदुपाडा		558.13	102.81	660.94					
21	साजा	साजा ग्रामीण		बीजा		साजा ग्रामीण		बीजा		365.55	52.85	418.4					
22	साजा	साजा ग्रामीण	कनई	कनई	7	साजा ग्रामीण	कनई	कनई	7	460.06	43.08	503.14					
23	साजा	साजा ग्रामीण		कनई		साजा ग्रामीण		कनई		90.71	8.72	99.43					
24	साजा	साजा ग्रामीण		मोतेसर		साजा ग्रामीण		मोतेसर		205.04	28.35	233.39					
25	साजा	साजा ग्रामीण		रैगा		साजा ग्रामीण		रैगा		137.22	27.47	164.69					
26	साजा	साजा ग्रामीण		हालुडी		साजा ग्रामीण		हालुडी		116.73	13.88	130.61					
27	साजा	साजा ग्रामीण	परलखेड	छपरी लेडी	8	साजा ग्रामीण	परलखेड	छपरी लेडी	8	180.46	24.19	204.65					
28	साजा	साजा ग्रामीण		पराबोड		साजा ग्रामीण		पराबोड		938.26	118.44	1056.70					
29	साजा	साजा ग्रामीण		पाटवा		साजा ग्रामीण		पाटवा		277.67	34.08	311.75					
30	साजा	साजा ग्रामीण		कावरी		साजा ग्रामीण		कावरी		331.88	39.22	371.1					
31	साजा	साजा ग्रामीण		तैदुपाडा		साजा ग्रामीण		तैदुपाडा		402.74	58.28	461.02					
32	साजा	साजा ग्रामीण	मोहला	पाटवा	11	साजा ग्रामीण	मोहला	पाटवा	11	337.69	36.69	374.38					
33	साजा	साजा ग्रामीण		मोहला		साजा ग्रामीण		मोहला		812.24	101.89	914.13					
34	साजा	मोहापाडा		जलपडी	18	साजा ग्रामीण	मोहापाडा	जलपडी	17	136.29	31.69	167.98					
35	साजा	मोहापाडा		देऊरगांव		साजा ग्रामीण		देऊरगांव		321.64	77.75	399.39					
36	साजा	मोहापाडा		बरागड़ा		साजा ग्रामीण		बरागड़ा		342.16	21.22	363.38					
37	साजा	मोहापाडा		मोहापाडा		साजा ग्रामीण		मोहापाडा		307.51	49.03	356.54					
38	साजा	मोहापाडा		सिधपुरी		साजा ग्रामीण		सिधपुरी		217.55	28.92	246.47					
योग										8543.65	1272.54	9816.19					
तहसील साजा रा.नि.मं. - बीजापाडा जिला - बेमेतरा																	
39	साजा	बीजापाडा	मेण्डरवाणी	कनपरा	1	बीजापाडा	मेण्डरवाणी	कनपरा	1	238.44	24.94	263.38					
40	साजा	बीजापाडा		चिन्दी		बीजापाडा		चिन्दी		401.33	108.37	509.7					
41	साजा	बीजापाडा		बैदरवाणी		बीजापाडा		बैदरवाणी		309.03	56.39	365.42					
42	साजा	बीजापाडा		मेण्डरवाणी		बीजापाडा		मेण्डरवाणी		607.38	88.14	695.52					
43	साजा	बीजापाडा		अपलीडीह		बीजापाडा		अपलीडीह		289.78	23.96	313.74					
44	साजा	बीजापाडा	खेवरा	खेवरा	12	बीजापाडा	खेवरा	खेवरा	12	581.18	75.38	656.56					
45	साजा	बीजापाडा		पडवीडीह		बीजापाडा		पडवीडीह		173.4	21.47	194.87					
46	साजा	बीजापाडा		बरागड़ा		बीजापाडा		बरागड़ा		281.88	42.79	324.67					
47	साजा	बीजापाडा				बीजापाडा				158.93	18.04	176.97	मोहापाडा (विरान ग्राम)				
योग										2581.96	391.02	2972.98					

48	साजा	बीजापौर	नवगवि महिला			बीजापौर	नवगवि महिला		287.5	38.89	326.39
49	साजा	बीजापौर	बीजापौर			बीजापौर	बीजापौर		339.49	27.88	367.37
50	साजा	बीजापौर	रघुपुर			रघुपुर	रघुपुर		171.2	10.25	181.45
51	साजा	बीजापौर	संजयपुर		13	बीजापौर	संजयपुर	13	213.44	18.08	231.5
52	साजा	बीजापौर	मुजफ्फरा			बीजापौर	मुजफ्फरा		274.36	36.52	310.88
53	साजा	बीजापौर	सोमपुर			बीजापौर	सोमपुर		372.56	31.94	404.5
54	साजा	बीजापौर	चौक			बीजापौर	चौक		502.36	71.08	573.42
55	साजा	बीजापौर	चौकटोरी		14	बीजापौर	चौकटोरी	14	222.06	39.01	259.07
56	साजा	बीजापौर	बीरपुर			बीजापौर	बीरपुर		604.8	112.06	716.86
57	साजा	बीजापौर	सोमपुर			बीजापौर	सोमपुर		387.10	62.42	449.52
58	साजा	बीजापौर	सोमपुर		15	बीजापौर	सोमपुर	15	339.40	54.69	394.09
59	साजा	बीजापौर	सोमपुर			बीजापौर	सोमपुर		219.55	29.84	249.39
60	साजा	बीजापौर	सोमपुर			बीजापौर	सोमपुर		645.91	86.70	732.61
61	साजा	बीजापौर	सोमपुर		18	बीजापौर	सोमपुर	18	205.68	29.15	234.83
62	साजा	बीजापौर	सोमपुर			बीजापौर	सोमपुर		235.72	38.11	273.83
63	साजा	बीजापौर	सोमपुर			बीजापौर	सोमपुर		167.38	13.29	180.67
64	साजा	बीजापौर	सोमपुर			बीजापौर	सोमपुर		220.18	39.43	259.71
65	साजा	बीजापौर	सोमपुर		31	बीजापौर	सोमपुर	31	354.01	52.61	406.62
66	साजा	बीजापौर	सोमपुर			बीजापौर	सोमपुर		390.34	42.64	432.98
67	साजा	बीजापौर	सोमपुर			बीजापौर	सोमपुर		186.58	30.7	217.28
योग									9421.57	1297.53	10719.10

हल्का बंदी 2022-23 तहसील देवकर जिला - बेमैतारा

तहसील देवकर रा.वि.म. - देवकर जिला - बेमैतारा											
68	देवकर	देवकर	अकलवाडा	अकलवाडा	20	देवकर	अकलवाडा	3	514.03	75.33	589.36
69	देवकर	देवकर	राजी	राजी		देवकर	राजी		851.46	130.54	982
70	देवकर	देवकर	देवकर	देवकर	28	देवकर	देवकर	11	855.57	188.53	1044.1
71	देवकर	देवकर	देवकर	देवकर		देवकर	देवकर		203.73	46.2	249.93
72	देवकर	देवकर	देवकर	देवकर	29	देवकर	देवकर	12	483.41	83.59	567
73	देवकर	देवकर	देवकर	देवकर		देवकर	देवकर		289.44	54.72	344.16
74	देवकर	देवकर	देवकर	देवकर		देवकर	देवकर		880.05	150.68	1030.73
75	देवकर	देवकर	देवकर	देवकर		देवकर	देवकर		213.59	54.4	267.99
76	देवकर	देवकर	देवकर	देवकर	30	देवकर	देवकर	13	124.6	35	159.6
77	देवकर	देवकर	देवकर	देवकर		देवकर	देवकर		335.85	48.23	444.08
योग									4791.73	867.22	5658.95

तहसील देवकर रा.वि.म. - देवकर जिला - बेमैतारा

78	देवकर	देवकर	देवकर	देवकर	23	देवकर	देवकर	6	214.66	13.82	228.48
79	देवकर	देवकर	देवकर	देवकर		देवकर	देवकर		567.4	117.71	685.11
80	देवकर	देवकर	देवकर	देवकर		देवकर	देवकर		500.61	65.92	566.53
81	देवकर	देवकर	देवकर	देवकर	24	देवकर	देवकर	7	232.34	70.94	303.28
82	देवकर	देवकर	देवकर	देवकर		देवकर	देवकर		318.84	42.07	360.91
83	देवकर	देवकर	देवकर	देवकर		देवकर	देवकर		322.87	45.33	368.2
84	देवकर	देवकर	देवकर	देवकर		देवकर	देवकर		456.32	34.64	490.96
85	देवकर	देवकर	देवकर	देवकर		देवकर	देवकर		235.92	37.18	273.1
86	देवकर	देवकर	देवकर	देवकर	25	देवकर	देवकर	8	356.36	47.09	403.45
87	देवकर	देवकर	देवकर	देवकर		देवकर	देवकर		435.11	61.54	496.65
88	देवकर	देवकर	देवकर	देवकर		देवकर	देवकर		323.4	41.38	364.78
89	देवकर	देवकर	देवकर	देवकर		देवकर	देवकर		676.8	136.29	813.09
योग									4641.23	713.91	5355.14

तहसील देवकर रा.वि.म. - देवकर जिला - बेमैतारा

90	देवकर	देवकर	देवकर	देवकर	17	देवकर	देवकर	1	260.73	26.46	287.19
91	देवकर	देवकर	देवकर	देवकर		देवकर	देवकर		139.15	32.62	171.77
92	देवकर	देवकर	देवकर	देवकर		देवकर	देवकर		275.5	34.36	309.86
93	देवकर	देवकर	देवकर	देवकर		देवकर	देवकर		861.87	52.58	914.45
94	देवकर	देवकर	देवकर	देवकर		देवकर	देवकर		312.06	20.99	333.05
95	देवकर	देवकर	देवकर	देवकर	18	देवकर	देवकर	2	160.44	16.39	176.83
96	देवकर	देवकर	देवकर	देवकर		देवकर	देवकर		267.7	37.73	305.43
97	देवकर	देवकर	देवकर	देवकर		देवकर	देवकर		623.36	94.57	717.93
98	देवकर	देवकर	देवकर	देवकर		देवकर	देवकर		191.31	35.73	227.04
99	देवकर	देवकर	देवकर	देवकर		देवकर	देवकर		247.01	31.42	278.43
100	देवकर	देवकर	देवकर	देवकर	21	देवकर	देवकर	4	246.24	52.89	299.13
101	देवकर	देवकर	देवकर	देवकर		देवकर	देवकर		224.55	47.4	271.95
102	देवकर	देवकर	देवकर	देवकर		देवकर	देवकर		292.45	64.35	356.8
103	देवकर	देवकर	देवकर	देवकर		देवकर	देवकर		262.15	64.67	326.82
104	देवकर	देवकर	देवकर	देवकर	22	देवकर	देवकर	5	544.5	88.9	633.4
105	देवकर	देवकर	देवकर	देवकर		देवकर	देवकर		324.66	60.35	385.01
106	देवकर	देवकर	देवकर	देवकर		देवकर	देवकर		309.78	61.89	371.67
107	देवकर	देवकर	देवकर	देवकर		देवकर	देवकर		586.56	113.94	700.5
108	देवकर	देवकर	देवकर	देवकर	23	देवकर	देवकर	9	189.62	29.26	218.88
109	देवकर	देवकर	देवकर	देवकर		देवकर	देवकर		266.52	21.21	287.73
110	देवकर	देवकर	देवकर	देवकर		देवकर	देवकर		708.17	60.96	769.13

111	देवसर	मौहापाटा	पेन्हावन		पाइलीट		पेन्हावन		274.23	27.99	302.22	
112	देवसर	मौहापाटा	बुंदेली	27	पाइलीट		पेन्हावन	10	506.01	78.94	584.95	
113	देवसर	मौहापाटा	रुक		पाइलीट		पेन्हावन		585.67	63.72	649.39	
योग									8020.24	1218.92	9239.16	
वहरीत का योग									89239.64	5868.58	45108.22	

जितेन्द्र शुक्ला,
कलेक्टर.